भारत सरकार
योजना मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1580
दिनांक 05.08.2024 को उत्तर देने के लिए

बहुआयामी गरीबी सूचकांक में प्रयुक्त संकेतक

1580. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों में देश में 248 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत आने वाले संकेतकों का ब्यौरा क्या है और इस सूचकांक की तुलना वैश्विक संकेतकों से कैसे की जा सकती है; और

(घ) सरकार गरीबी के इन आंकड़ों का उपयोग किस प्रकार करने जा रही है और देश में अधिक से अधिक लोगों की गरीबी समाप्त करने के लिए किस प्रकार आगे बढ़ने की योजना बना रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) जी, हां, नीति आयोग द्वारा 2005-06 से प्रकाशित भारत में बहुआयामी गरीबी पर चर्चा पत्र के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी का अनुमान 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया है, जिसका अभिप्राय है कि इस अवधि के दौरान 248.2 मिलियन लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) में 12 संकेतक हैं। ये संकेतक हैं- पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, बैंक खाते और परिसंपत्ति। वैश्विक एमपीआई में बैंक खाता और मातृ स्वास्थ्य को छोड़कर बाकी सभी संकेतक शामिल हैं। इसलिए, वैश्विक एमपीआई भारत में बहुआयामी गरीबी की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली राष्ट्रीय पद्धति से लगभग समान है।

(घ) बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख अंतःक्षेपों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), पीएम उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई), पीएम-जन धन योजना, कौशल भारत मिशन, पीएम मुद्रा योजना, स्टार्ट अप इंडिया और स्टार्ट अप गारंटी, सौभाग्य, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर आदि शामिल हैं।

****

अनुलग्नक

"बहुआयामी गरीबी सूचकांक में प्रयुक्त संकेतक" के संबंध में श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी द्वारा दिनांक 05.08.2024 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1580 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(ख) पिछले 10 वर्षों (2013-14 से 2022-23 तक) के राज्य-वार गरीबी अनुमान

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल गणना का अनुपात (%)		बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या (अनुमानित) लाख में
		2013-14	2022-23	
1	आंध्रप्रदेश	*	4.19	*
2	अरुणाचल प्रदेश	29.11	10.05	2.98
3	असम	36.97	14.47	80.36
4	बिहार	56.34	26.59	377.09
5	छत्तीसगढ़	35.42	11.71	71.55
6	गोवा	5.15	0.37	0.75
7	गुजरात	21.53	9.03	89.41
8	हरियाणा	*	5.30	*
9	हिमाचल प्रदेश	10.14	3.88	4.67
10	झारखंड	47.13	23.34	93.92
11	कर्नाटक	16.55	5.67	73.64
12	केरल	1.24	0.48	2.72
13	मध्य प्रदेश	41.57	15.01	230.00
14	महाराष्ट्र	18.06	5.48	159.07
15	मणिपुर	20.53	5.37	4.89
16	मेघालय	37.08	25.46	3.89
17	मिजोरम	12.47	3.77	1.08
18	नागालैंड	29.82	11.76	4.03
19	ओडिशा	34.28	11.07	102.78
20	पंजाब	*	4.35	*
21	राजस्थान	33.86	10.77	187.12
22	सिक्किम	6.07	2.10	0.27

23	तमिलनाडु	7.16	1.43	43.98
24	तेलंगाना	*	3.76	*
25	त्रिपुरा	20.94	11.49	3.92
26	उत्तर प्रदेश	42.59	17.40	593.69
27	उत्तराखंड	20.85	6.92	16.21
28	पश्चिम बंगाल	25.98	8.60	172.18
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	*	1.63	*
30	चंडीगढ़	*	2.62	*
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	*	6.06	*
32	दिल्ली	5.64	2.97	5.69
33	जम्मू एवं कश्मीर	*	2.81	*
34	लद्दाख	*	1.73	*
35	लक्षद्वीप	*	0.84	*
36	पुदुचेरी	*	0.58	*
	भारत	**29.17**	**11.28**	**2482.16**

* तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर हुआ था। इस प्रकार, राज्य वर्ष 2015-16 और 2019-21 में एक प्रथक नमूना इकाई के रूप में अस्तित्व में था, लेकिन 2005-06 में ऐसा नहीं था।

जम्मू और कश्मीर के 2005-06 के अनुमानों में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दोनों शामिल हैं। इस प्रकार 2005-06 में लद्दाख के लिए प्रथक अनुमान मौजूद नहीं हैं। हालाँकि, वर्ष 2015-16 और 2019-21 के लिए लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर के लिए अलग-अलग अनुमान मौजूद हैं।

संघ राज्य क्षेत्र: अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी का एनएफएचएस 2005-06 में नमूना नहीं लिया गया था। एनएफएचएस 3 (2005-06) में, चंडीगढ़ राज्य का गठन करने वाली नमूना इकाई दो पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा का हिस्सा थी। जबकि 2015-16 और 2019-21 में चंडीगढ़ के अलग-अलग अनुमान थे।

ये अनुमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या अनुमानों पर आधारित हैं।

*****